

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महाप्रशासक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 05 फरवरी, 2009

विषय- महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या- 34/xxxvi(1)एक/08-582/2001 दिनांक 28 जनवरी, 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1-3-2009 से 28-2-2010 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या- 16- एक (1) / न्याय अनुभाग/03 दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा किया गया था ।

2- उक्त न्यायालयों के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-800-अन्य व्यय-07-महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सम्पत्ति कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7-11-92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधित्व किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव

संख्या- 33 (1)/xxxvi(1)एक/09-582/2001 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड नाजरा, देहरादून ।
- 2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 3- वरिष्ठ कौषाधिकारी, नैनीताल ।
- 4- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एनआई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(के०पी० पाटौली)
अनु सचिव